कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज समागम, मदुरै.. 7

राज्यों में भाजपा 'प्रशिक्षण महाभियान'... 8

सरकार की उपलब्धियां

दूसरी हरित क्रांति को साकार करने का आह्वान.................................... 10

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ.............................. 11

भारत–बांग्लादेश समझौता.. 13

वैचारिकी

राजनीतिक दलों के लिये आचार–संहिता

पं. दीनदयाल उपाध्याय.. 14

श्रद्धांजलि

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम नहीं रहे.. 16

भारत ने एक हीरा खो दिया है

– नरेन्द्र मोदी.. 17

लेख

असहमति या व्यवधान – जीएसटी पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति

– अरुण जेटली.. 19

अन्य

भारत सरकार और एनएससीएन के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता....... 22

परिवर्तन रैली, मुजफ्फरपुर (बिहार).. 26

तापी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण को शुरू करने पर जोर 28

'मन की बात'... 30

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाएं!

गौतम बुद्ध उवाच, 'आप दीपक बनो'

भगवान बुद्ध जब मृत्युशैय्या पर अंतिम सांसें गिन रहे थे कि किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गौतम बुद्ध ने अपने नजदीक बैठे शिष्य आनंद से पूछा, 'आनंद कौन रो रहा है।'

आनंद ने कहा, 'भंते! भद्रक आपके अंतिम दर्शन के लिए आया है।' बुद्ध ने कहा, 'तो उसको मेरे पास बुला लो। आते ही भद्रक फूट-फूट कर रोने लगा, उसने कहा आप नहीं रहेंगे तो हमें ज्ञान का प्रकाश कौन दिखाएगा।'

बुद्ध ने भद्रक से कहा, 'भद्रक प्रकाश तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो अज्ञानी है इसे देवालयों, तीर्थों, कंदराओं या गुफाओं में भटकते हुए खोजने का प्रयत्न करते हैं। वे अंत में निराश होते हैं। इसके विपरीत मन, वाणी और कर्म से एकनिष्ठ होकर जो साधना में निरंतर लगे रहते हैं। उनका अंत: करण स्वयं दीप्त हो उठता है। इसलिए भद्रक, 'आप दीपक बनो।' यही मेरा जीवनदर्शन है जिसे मैं आजीवन प्रचारित करता रहा।

(अमर उजाला से साभार)

पाथेय

राष्ट्र मंदिर

राष्ट्र की भी एक आत्मा होती है। उसका एक शास्त्रीय नाम है। इसे 'चिति' कहा गया है। मग्डूगल के अनुसार, समूह की कोई मूल प्रकृति होती है। वैसे ही 'चिति' किसी समाज की वह प्रकृति है जो जन्मजात है तथा जो ऐतिहासिक कारणों से नहीं बनी। चिति तो मूलभूत होती है। चिति को लेकर प्रत्येक समाज पैदा होता है और उस समाज की संस्कृति की दिशा चिति निर्धारित करती है, अर्थात् जो चीज चिति के अनुकूल होती है वह संस्कृति में सम्मिलित कर ली जाती है। चिति वह मापदण्ड है जिससे हर वस्तु को मान्य अथवा अमान्य किया जाता है। यही राष्ट्र की आत्मा है। इसी आत्मा के आधार पर राष्ट्र खड़ा होता है और यही आत्मा राष्ट्र के प्रत्येक श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण द्वारा प्रकट होती है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

कांग्रेस हंगामा कर अपना भाग्य नहीं बदल सकती

समाधकीय

एक ओर जब भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर अपनी नई पहचान अंकित कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कुछ विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार के मार्ग को अवरूद्ध कर अपनी असफलता छिपाना चाहते हैं। कांग्रेस को अब समझ लेना चाहिए कि 'गतिरोधक' बनकर वह अपने आप को बचा नहीं पायेगी। अब उसे स्वयं को संसदीय मूल्यों एवं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का आदर करना सीखना पड़ेगा और लोकसभा में हुई करारी हार की वास्तविकता को स्वीकारते हुए कांग्रेस को 'रचनात्मक विपक्ष' की भूमिका में अब आ जाना चाहिए। यह सच है कि कांग्रेस देश को कोई 'रचनात्मक शासन' नहीं दे सकी परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे 'रचनात्मक विपक्ष' की अपनी भूमिका से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए। हंगामा कर अवरोध खड़ा करके कांग्रेस अब राजनैतिक रोटियां नहीं सेक सकती, जनता अब राजनीति में सकरात्मकता एवं रचनात्मकता देखना चाहती है। राष्ट्र की प्रगति में गतिरोध बन कांग्रेस स्वयं को लोगों के नजर में और अधिक छोटा कर रही है।

जिस तरह से संसद में हंगामे से कांग्रेस ने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, व्यवस्था बहाल करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। स्पष्टत: तेज गति से हो रही देश की प्रगति में यह किसी प्रकार से गतिरोध पैदा करने का प्रयास है। देश-दुनिया में जिस प्रकार भाजपा-नीत राजग सरकार सफलता के झंडे गाड़ रही है और अपार समर्थन प्राप्त कर रही है उससे कांग्रेस का घबराना स्वाभाविक है। कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाहती है, वह चाहती है कि उसकी भी कोई पहचान बने। लेकिन जिस नकारात्मक ढंग से इसने अपने आपको पेश किया है उससे उसकी छवि पर और अधिक बट्टा लगा है। संसद को लगभग तीन सप्ताह तक बाधित करने के दोष तले कांग्रेस दब चुकी है। इस राष्ट्रीय क्षति की जिम्मेदारी कांग्रेस के माथे मढ़ा जा चुका है। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। इतना ही नहीं कांग्रेस ने संसदीय गरिमा की सभी मर्यादाओं को भी लांघ दिया। लोकसभा अध्यक्ष के सामने संसद की गरिमा पुनर्स्थापित करने के लिए कांग्रेस के 25 सदस्यों को निलंबित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।

संसद लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के प्रभावी कार्य के लिये इसका मर्यादित रूप में चलना आवश्यक है। हां, यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न मतों पर चर्चा एवं बहस की जाती है लेकिन इसके कार्यवाही की अपनी एक गरिमापूर्ण व्यवस्था है। विरोध जताने के लिए राजनैतिक दल स्व-अनुशासन का ध्यान लोकतंत्र के व्यापक संदर्भ में रखते हैं। हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है और लोगों के विश्वास को इसमें निरंतर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जिस तरह का हंगामा कांग्रेस संसद में कर रही है वह परिपक्व लोकतंत्र के स्वीकार्य मर्यादाओं में नहीं आता। इस तरह के कार्य से कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास तो और टूटेगा ही परन्तु इससे राष्ट्रीय हितों की भी क्षति होगी। यदि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसके हंगामे से मोदी सरकार की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आने वाली है तो उसका भगवान ही मालिक है। यह मोदी-सरकार का अहित नहीं कर रही, राष्ट्रीय हितों पर हमला कर रही है और स्वयं को जनता के सामने बेनकाब कर रही है।

राष्ट्र आशा एवं विश्वास के साथ प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। राष्ट्र के पास अब नरेन्द्र मोदी जैसा नेतृत्व है जो देश को विकसित एवं गौरवशाली बनाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। भाजपा-नीत राजग के अभिनव पहलों से लोग भारी संख्या में उत्साहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर

'एक अनकही कहानी : केरल में कम्युनिस्ट हिंसा' विषय पर प्रदर्शनी

यह प्रदर्शनी कम्युनिस्ट हिंसा को बेनकाब करेगी : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 'एक अनकही कहानी: केरल में कम्युनिस्ट हिंसा' विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि आज केरल में पार्टी विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है जबकि हमारी प्राथमिकता केरल को विकास के पथ पर अग्रसर करना है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा और विकास की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता उन पर कातिलाना हमले करते हैं और ऐसा केवल केरल में ही नहीं हो रहा है। वरन यह हर उस जगह होता रहा है जहाँ उनकी सरकारें रही हैं या जिन क्षेत्रों में वह प्रभावी हैं और यही उनकी आदत है। वह हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि केरल के लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों पर कब तक विश्वास किया जा सकता है जो राष्ट्रवाद और विकास के लिए काम करने वाले लोगों के ऊपर घातक हमले करते हैं।

उन्होंने कहा कि हिंसा और लोकतंत्र दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते।

श्री शाह ने कहा कि इस प्रदर्शनी को दिल्ली में आयोजित कराने का यह औचित्य था कि सबके सामने ये बात लाई जा सके कि केरल में किस तरह से वैचारिक लड़ाई को बर्बर हमलों में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि जो आज केरल में सत्ता में हैं या जो सत्ता में आते रहे हैं, उनकी वजह से वहां देशभक्तों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि देशभक्तों के साथ केरल में कितना अमानवीय अत्याचार हो रहा है। श्री अमित शाह ने इस प्रदर्शनी के आयोजकों की तारीफ करते हुए कहा कि ये केरल में सत्ता में लगातार रहने वाले लोगों द्वारा देशभक्तों और राष्ट्रवाद की वैचारिक लड़ाई लड़ने वालों के साथ किये गए क्रूर बर्ताव को बेनकाब करेगा। ■

➔ भारत को अब आदर से देखा जा रहा है एवं नरेन्द्र मोदी के पहलों का लाभ अब देश को मिलना शुरू हो गया है। ऐसे समय में कांग्रेस को इन पहलों के समर्थन में मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। हंगामे वाली राजनीति से कांग्रेस शायद इस लायक भी ना बचे कि दूसरा चुनावी झटका झेल पाये। इसे अब 'रचनात्मक विपक्ष' की भूमिका में आ जानी चाहिए एवं पार्टी को समाज में सकारात्मक भूमिका के लिये तैयार करना चाहिये। इसे भाजपा से सबक लेना चाहिये जो अमित शाह की दृष्टिपूर्ण नेतृत्व में न केवल विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गई है बल्कि ऐसे कदम उठा रही है ताकि यह सर्वाधिक सुसंगठित, सकरात्मकता से भरी कार्य आधारित पार्टी बने। हंगामा से कांग्रेस के भाग्य का दरवाजा नहीं खुल सकता, इसे अब समझ लेना चाहिये। ■

संगठनात्मक गतिविधियां : देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज समागम, मदुरै

एक नए समग्र समाज का निर्माण करना चाहिए : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 6 अगस्त को तमिलनाडु के मदुरै में देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज के समागम में भाग लिया और भारी संख्या में उपस्थित लोगों को सम्बोधित किया।

उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज विभिन्न समुदायों के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपका निर्णय समाज को एक नई दिशा दिखायेगा।

उन्होंने देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज का आह्वान करते हुए कहा कि आपको जाति प्रथा का उन्मूलन कर समाज के खोये हुए गौरव को पुन:स्थापित करके सभी जातियों के समाज के गौरव को इकट्ठा करके देश के गौरव से इसे जोड़कर एक नए समग्र समाज का निर्माण करना चाहिए। समागम को सम्बोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि आपके समाज द्वारा किये गए प्रयासों के फलस्वरूप समाज में एक नई सोच का निर्माण करेगी।

श्री शाह ने मदुरै घोषणापत्र की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसका समर्थन करती आई है और हमेशा से आपके साथ है।

उन्होंने समागम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं इस सामाजिक मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि तमिलनाडु एक ओर तो विकसित राज्यों की सूची में शामिल है वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट राज्यों की सूची में भी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विकास और भ्रष्टाचार कभी भी साथ नहीं चल सकते।

श्री शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार ने तमिलनाडु की विकास क्षमता को आधा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि तमिलनाडु से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो तमिलनाडु को भारत का सबसे विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्री शाह ने मीनाक्षी मंदिर को भारत के समृद्धि का साक्षी बताया और जनता का आह्वान करते हुए कहा कि आज हम सब खासकर तमिलनाडु के युवा यह संकल्प करें कि भ्रष्टाचार को यहाँ से समूल नष्ट करना है और तमिलनाडु को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है।

तमिलनाडु एक ओर तो विकसित राज्यों की सूची में शामिल है वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट राज्यों की सूची में भी है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि विकास और भ्रष्टाचार कभी भी साथ नहीं चल सकते।

उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले एक वर्ष से कुछ अधिक समय में पूरी दुनिया में भारत का गौरव पुनर्स्थापित किया है और हरेक भारतीय के सिर को गर्व से ऊँचा करने का कार्य किया है।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी जी को समाज के हर वर्ग के उत्थान के हेतु किये गए प्रयासों के लिए आप सबका आशीर्वाद सतत रूप से मिलते रहना चाहिए।

अपने उद्बोधन के अंत में उन्होंने देवेंद्रकुला वेलालर्स समाज को हृदय से साधुवाद देते हुए कहा कि आपके प्रयास और आपका गौरवपूर्ण निर्णय अनुकरणीय है और मैं देवाधिदेव इंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको हमेशा शक्ति दे और आपके गौरव की स्थापना में कोई बाधा न रहे। ■

राज्यों में भाजपा 'प्रशिक्षण महाभियान' कार्यशालाओं के आयोजन की शुरूआत

राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करने के साथ ही भाजपा ने तीन सतही व्यवस्था तैयार करने की रणनीति बनाई थी, अर्थात् सदस्यता महाभियान, सम्पर्क महाभियान तथा प्रशिक्षण महाभियान की रणनीति तैयार की है ताकि सदस्यता अभियान को पूरी तरह सफल बनाया जा सके। विशेष उल्लेखनीय यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरूआत की। सदस्यता महाभियान की शुरूआत नई दिल्ली में 1 नवम्बर 2014 को शुरू किया गया और इस अवसर पर श्री मोदी ने स्वयं को पार्टी का प्रथम सदस्य बनाया।

राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के बड़े स्तर पर सफल होने के बाद भाजपा विश्व में पहली ऐसी राजनैतिक बड़ी पार्टी बन गई है जिसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से भी कहीं अधिक है। इसके बाद पार्टी के नए नामित सदस्यों के लिए संगठन ने नई दिल्ली में 1 मई 2015 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निवास पर 'महा सम्पर्क अभियान' की शुरूआत की। महा सम्पर्क अभियान के अन्तर्गत पार्टी के संगठन-नेताओं तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी 11 करोड़ नए सदस्यों के घर प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक दी, जिन्होंने हाल ही में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उनकी सदस्यता का सत्यापन किया। महाभियान देश के विभिन्न भागों में चल रहा है और यह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा।

इसी बीच, तीन सतही सदस्यता अभियान के तीसरे और आखिरी चरण में अर्थात् 'प्रशिक्षण महाभियान की शुरूआत विभिन्न राज्यों में 1 अगस्त 2015 में साथ ही शुरू की गई। कार्यक्रम के अनुसार पार्टी ने लगभग 15 लाख सक्रिय सदस्यों के प्रशिक्षण का विचार बनाया है।

प्रशिक्षण महाभियान चार सतही कार्यक्रम है। योजना के अनुसार देश के 11000 से अधिक मण्डलों में पार्टी के सक्रिय कार्यक्रम बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे तथा देश के सभी 650 जिलों में ये शिविर लगेंगे। राज्य स्तर शिविर तीसरा चरण रहेगा और सभी राज्यों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में अधिक से अधिक 150 व्यक्ति होंगे। यदि यह संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो अधिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण महाभियान चार सतही कार्यक्रम है। योजना के अनुसार देश के 11000 से अधिक मण्डलों में पार्टी के सक्रिय कार्यक्रम बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे तथा देश के सभी 650 जिलों में ये शिविर लगेंगे। राज्य स्तर शिविर तीसरा चरण रहेगा और सभी राज्यों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में अधिक से अधिक 150 व्यक्ति होंगे। यदि यह संख्या 150 से अधिक हो जाती है तो अधिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मंडल स्तर कार्यक्रम की अवधि दो दिन और एक रात की होगी, जिला स्तर पर यह दो रात और तीन दिन तथा राज्य स्तर पर तीन रात एवं चार दिन की होगी। कार्यक्रम में पूरी अवधि के दौरान शिविर में रहना आवश्यक होगा और सभी शिविरों की शैली कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसी रहेगी। राज्यों में सभी शिविर साथ ही साथ चलेंगे और अंत में एक राष्ट्रीय स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण को पूर्णत: सफल बनाने के लिए संगठन ने भारी संख्या में बने नए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों का चुनाव किया है। हाल ही में प्रशिक्षकों के लिए तीन दिन की राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

के नेतृत्व में किया गया और राष्ट्रीय शिविर ने भावी रोडमैप तैयार किया है और इनमें क्या-क्या विषय लिए जाएंगे और कार्यक्रम के प्रशिक्षण कंटेंट क्या-क्या होंगे, इन्हें भी तैयार किया गया है।

पहली बार, भाजपा ने इतने बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है और यह पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चार महीनों में पूरा किया जाएगा।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तीन चरणों की व्यवस्था होगी, अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर आयोजन होगा तथा कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित कार्यकर्ता मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। वर्तमान में प्रशिक्षक प्रशिक्षण राज्य कार्यशालाओं में विभिन्न राज्यों में आयोजित होगा। राज्य कार्यशालाएं पहले ही त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आयोजित हो चुके हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में वहां की स्थानीय घटनाओं के अनुसार बाढ़ और चुनाव स्थिति को देखते हुए तारीखों में परिवर्तन किया है। किन्तु, राज्य कार्यशालाएं इस महीने के अन्त तक अवश्य पूरी करनी होंगी।

राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें विभिन्न राज्य कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, सर्वश्री शिव प्रकाश, वी. सतीश, महेश चन्द्र शर्मा, कलराज मिश्रा, थावरचन्द्र गहलोत, प्रेम कुमार धूमल, जे.पी. नड्डा, अविनाश राय खन्ना, शांता कुमार, रघुनाथ कुलकर्णी, रवीन्द्र साठे, सुरेश पुजारी, सुनील देवधर, महेन्द्र सिंह, रमन डेका, जितेन्द्र सिंह, दिनेश शर्मा, अनिल जैन, भगत सिंह कोशियारी, महेन्द्र पांडे, त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती सुधा यादव और श्रीकांत शर्मा विभिन्न कार्यशालाओं में भाग ले चुके हैं।

प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तीन चरणों की व्यवस्था होगी, अर्थात् राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर आयोजन होगा तथा कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित कार्यकर्ता मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। वर्तमान में प्रशिक्षक प्रशिक्षण राज्य कार्यशालाओं में विभिन्न राज्यों में आयोजित होगा। राज्य कार्यशालाएं पहले ही त्रिपुरा, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आयोजित हो चुके हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में वहां की स्थानीय घटनाओं के अनुसार बाढ़ और चुनाव स्थिति को देखते हुए तारीखों में परिवर्तन किया है। किन्तु, राज्य कार्यशालाएं इस महीने के अन्त तक अवश्य पूरी करनी होंगी।

नए तथा पुराने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की पूरी कवायद के पीछे प्रमुख विचार यही रहा है कि उनमें संगठन की विचारधारा, आदर्शों तथा मूल्यों को कार्यकर्ताओं में भरा जाए। पार्टी की विचारधारा के अलावा कार्यकर्ताओं को ग्यारह प्रमुख विषयों तथा दो स्थानीय मुद्दों पर प्रशिक्षित किया जाएगा अर्थात् उन्हें पार्टी के इतिहास, सरकारी उपलब्धियां, 'हमारा विचार परिवार', संगठनात्मक ढांचा और पार्टी की कार्य संस्कृति, 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद', 'एकात्म मानवदर्शन' सम्बन्धी जानकारी, कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास, मीडिया सम्बन्धों, राष्ट्र के समक्ष सामाजिक मीडिया और सामाजिक मीडिया और चुनौतियां आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रत्येक राज्य के उस राज्य की विशिष्ट सामाजिक-राजनैतिक पहलुओं को उजागर किया जाएगा और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों पर इन सक्रिय कार्यकर्ताओं को अद्यतन जानकारी देने के लिए सत्र रखा जाएगा तथा भाजपा-शासित राज्यों में अनेक नवीन पहल की गई हैं- उनकी भी जानकारी दी जाएगी।

योजना के अनुसार 'प्रशिक्षण अभियान' को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पार्टी ने अपने सभी आधुनिक तकनीकों और उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग करेगी। नए कार्यकर्ताओं के सामने प्रत्येक मुद्दे को प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए पार्टी ने डाक्युमेंट्री तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से टेक्नालॉजी उपकरणों का इस्तेमाल करने का विचार बनाया है। ■

(श्री आर. बालाशंकर, सदस्य प्रशिक्षण महाभियान से कमल संदेश के रामप्रसाद त्रिपाठी की बातचीत पर आधारित)

कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत : प्रधानमंत्री

दूसरी हरित क्रांति को नई दृष्टि और नये आयामों के साथ साकार करने का आह्वान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जुलाई को पटना में कहा कि राष्ट्र दूसरी हरित क्रांति के लिए लम्बे समय तक इंतजार नहीं कर सकता और यह पूर्वी भारत से ही आनी चाहिए। श्री मोदी पटना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) के 87 वें स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री

ने बजट की कमी के बावजूद उनके काम के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की प्रशंसा की और साथ ही उन्होनें कृषि क्षेत्र में 'प्रयोगशाला से खेतों तक' वैज्ञानिक नवाचारों की जरूरत पर बल दिया जिससे कि किसान उनका लाभ उठा सकें।

माननीय प्रधानमंत्री ने आधुनिक समय में कृषि से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए नई दृष्टि, नये आयाम और नये उद्देश्यों के साथ दूसरी हरित क्रांति का आरंभ करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों एवं योजनाकारों का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों के योगदान की प्रशंसा करते हुए सुझाव दिया कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी कृषि उत्पादों को पहचान कर उन पर शोध कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने इस विचार को पुनः दुहराया कि अपार प्राकृतिक संसाधनों और कृषि प्रयोग की इच्छा से भरपूर पूर्वी भारत के किसानों में सामर्थ्य है कि वे दूसरी हरित क्रांति की अगुआई कर सकें।

प्रधानमंत्री ने आईसीएआर द्वारा स्थापना दिवस को पटना में आयोजित करने की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम बिहार में, 1905 में स्थापित कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा देश में व्यवस्थित कृषि अनुसंधान कार्य की शुरुआत हुई थी।

'प्रयोगशाला से खेत तक' के कार्यक्रम पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि वे किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के विकास व प्रसार में अपना भागीदार बनाएं। वैज्ञानिकों द्वारा गांवों को अपनाने से किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि आईसीएआर ने 'प्रयोगशाला से खेत तक' को साकार करते हुए, इस विचार को योजना का स्वरूप प्रदान किया और आज इनका शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नहरों, अनाज कोठारों जैसी बुनियादी संरचनाओं के निर्माण के लिए वास्तुकला विशेषज्ञों के साथ संबंध विकसित किया जाए, जिससे इस संदर्भ में विकसित नई तकनीकों का लाभ कृषि जगत उठा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गांवों में प्रचुर पारंपरिक ज्ञान विद्यमान है, जिसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि प्रति हेक्टर उत्पादकता वृद्धि के लिए वे अपने ज्ञान को किसानों की दक्षता के साथ जोड़ें। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष दालों और तिलहन की बढ़ी जोत पर प्रसन्नता जाहिर की।

प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार पर जोर दिया जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और शहद के वैश्विक बाजार का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने जैविक खेती को व्यापक बनाने का भी सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने केसरिया, हरी, श्वेत और नीली क्रांति के लिए वैज्ञानिकों का आह्वान किया जो क्रमशः ऊर्जा, कृषि, दूध और मात्स्यिकी से संबंधित हैं।

प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के एक हाल ही के एपिसोड का

शेष पृष्ठ 12 पर

सरकार की उपलब्धियां

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जुलाई 2015 को पटना में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ किया। इस योजना से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था में न केवल सुधार होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। ग्रामीण, कृषि क्षेत्र और कॉमर्शियल कार्यों में लगे सभी प्रकार के लोगों को इस योजना से लाभ होगा। केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर डीडीयूजीजेवाई योजना को गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई इसी तरह की योजना से प्रेरणा मिली। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में उन सुधारों को शुरू किया जा सकेगा जिनकी लम्बे समय से प्रतीक्षा है। इसमें ग्रामीण इलाकों में सभी स्तरों पर मानीटरिंग सहित फीडर सेपरेशन (ग्रामीण परिवार और कृषि) तथा सब-ट्रांसमीशन और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इससे गांव के घरों में 24 घंटे बिजली प्रदान

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)-एक अवलोकन

पृष्ठभूमि

- देश के ग्रामीण कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं (घरेलू और गैर-घरेलू भार) को आमतौर पर स्थानीय वितरण नेटवर्क से सेवाएं मिलती हैं। देश के अनेक ग्रामीण इलाकों को अपर्याप्त बिजली आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है, परिणामस्वरूप जनोपयोगी वितरण सेवाओं को लोड शेडिंग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसके कारण कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली की आपूर्ति प्रभावित होती है।
- ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ताओं के बदलते आधार, जीवन स्तर में सुधार के कारण बिजली की मांग दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है जिसके लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता है।
- वितरण कम्पनियों की वित्तीय हालत खराब होने के कारण वितरण नेटवर्क में निवेश कम हुआ है। परिणामस्वरूप विश्वसनीयता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपूर्ति-वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना जरूरी है।
- बिजली वितरण की व्यावसायिक व्यावहारिकता में सुधार के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों की मानीटरिंग करने की जरूरत है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य:

- सभी गांवों का विद्युतीकरण करना
- किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए फीडर सेपरेशन और अन्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति
- ब-ट्रांसमीशन और वितरण नेटवर्क में सुधार ताकि आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाया जा सके।

करने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद मिलेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पूर्व की योजना यानी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में नई योजना में शामिल कर लिया गया है।

योजना के प्रमुख घटकों में फीडर सेपरेशन, सब-ट्रांसमीशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, सभी स्तरों पर मानीटरिंग (इनपुट प्वाइंट, फीडरों और वितरण ट्रांसफार्मरों), सूक्ष्म ग्रिड तथा ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं। इन सभी को आरजीजीवीवाई के अंतर्गत पहले ही मंजूरी मिली हुई है और इन्हें पूरा किया जाना है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योजना में 76,000 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है जिसमें भारत सरकार 63,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। कुल 14,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जिनमें से 5,827 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को बिहार राज्य के लिए मंजूर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कृषि प्रधान राज्य बिहार को फीडर सेपरेशन के कार्यों से लाभ मिलेगा। हजारों किलोमीटर की नई लाइनें बिछाई जाएंगी और सैंकड़ों नए सब-स्टेशन लगाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और सभी घरों को बिजली मिल सकेगी।■

नुकसान कम करने के लिए मानीटरिंग

वित्तीय प्रावधानः

- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए योजना में 76,000 करोड़ रुपये खर्च रखा गया है जिसमें से भारत सरकार 63,000 करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
- कुल 14,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से 5827 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की बिहार राज्य के लिए मंजूरी दी गई है।

योजना से लाभ

- सभी गांवों और घरों को बिजली मिलेगी।
- कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी होगी।
- बिजनेस और लघु तथा घरेलू उद्यम बढ़ेंगे जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग (एटीएम) सेवाओं में सुधार।
- रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल आदि तक पहुंच में सुधार।
- बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुरक्षा बेहतर होगी।
- स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस थानों आदि में बिजली की पहुंच।
- ग्रामीण इलाकों के विस्तृत विकास के अधिक अवसर मिलेंगे।

पृष्ठ 10 का शेष...

उल्लेख किया जिसमें उन्होंने दालों और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत के बारे में बात की थी। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस साल दालों और तिलहन के बुवाई क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का उद्देश्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पुरस्कार-2014 प्रदान किये और पांच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल उत्कृष्ट भाकृअनुप संस्थान पुरस्कार, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार (राष्ट्रीय), कृषि में विविधता के लिए एन. जी. रंगा कृषक पुरस्कार तथा उत्कृष्ट कृषि पत्रकारिता के लिए चौ. चरण सिंह सिंह पुरस्कार प्रदान किये। इस अवसर पर उन्होंने भाकृअनुप द्वारा विकसित मृदा परीक्षण किट को जारी करते हुए किसानों को वितरित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा भा.अनुप की नई योजनाओं आर्या, स्टूडेंट रेडी तथा मेरा गाँव मेरा गौरव का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने आईसीएआर विजन-2050 को भी जारी किया, जिसमें वर्ष 2050 तक देश में खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। परिषद के अंतर्गत देश में कार्यरत 100 संस्थानों के लिए भी विजन-2050 विकसित किया गया है। बिहार के राज्यपाल श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहनभाई कुंदरिया और श्री संजीव कुमार बाल्यान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ■

भारत-बांग्लादेश समझौताः

51,000 राष्ट्रविहीन लोगों को मिला देश और नागरिकता

भारत और बांग्लादेश के बीच 31 जुलाई की मध्य रात्रि को बस्तियों का ऐतिहासिक आदान-प्रदान किया गया। इस समझौते के साथ ही 162 बस्तियों के 51,000 से अधिक राष्ट्रविहीन लोगों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित 111 बस्तियां बांग्लादेश में शामिल हो गयीं जबकि 51 भारत में। एक अनुमान के मुताबिक, इस फैसले की जद में आने वाली भारतीय कॉलोनियों में करीब 37 हजार लोग रहते हैं। वहीं बांग्लादेशी कॉलोनियां में 14 हजार लोग रहते हैं। भारत की कॉलोनियों में रहने वाले करीब 37 हजार लोगों में से 980 लोग भारत लौट रहे हैं।

दरअसल, 18वीं सदी में राजाओं के समझौतों के कारण अस्तित्व में आयी बस्तियों की यह विसंगति दो शताब्दी से चली आ रही थी। ये बस्तियां एक देश की हैं और लोग रहते हैं दूसरे देश में। इन बस्तियों के लोग जन सुविधाओं से वंचित थे और खराब हालत में जी रहे थे। भारत, पाकिस्तान और अंत में बांग्लादेश की आजादी के बाद भी इनकी समस्या को किसी ने दूर नहीं किया। समझौते लागू होने के साथ ही अब यह विसंगति दूर हो गयी है। चूंकि देश भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर शोक मना रहा था, इसलिए सरकारी स्तर पर बस्तियों के आदान-प्रदान पर कोई समारोह नहीं हुआ। बस्तियों का आदान-प्रदान इसी साल छह जून को ढाका में भारत और बांग्लादेश के बीच एक करार पर दस्तखत के बाद हो रहा है। इस दौरे की खास बात यह भी थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश गई थीं जबकि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के बांग्लादेश दौरे के वक्त उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते की तुलना बर्लिन की दीवार गिरने वाली घटना से करते हुए कहा था कि अगर इस तरह का समझौता दुनिया में कहीं और हुआ होता तो इसे नोबेल सम्मान मिलता, लेकिन हम गरीब देश हैं इसलिए कोई नहीं पूछेगा। इस समझौते को भारत में मई महीने में संसद ने पास किया था।

इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बांग्लादेश में कहा था कि भारत की ससंद में सभी दलों के द्वारा पारित किए गए इस समझौते से पता चलता है कि बांग्लादेश और भारत कितने अहम सहयोगी हैं। ■

समझौते की पृष्ठभूमि

- **भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला-बदली का पहला समझौता 16 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री श्री मुजीबुर्रहमान के बीच हुआ था।**
- **बांग्लादेश की संसद ने इस समझौते को 1974 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन समझौते के लिए जमीन की अदला-बदली के लिए भारत में संविधान संशोधन की जरूरत हुई, जिसके चलते समझौते को आखिरी रूप देने में इतना वक्त लग गया।**
- **छह जून, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष श्रीमती शेख हसीना की मौजूदगी में बस्तियों के आदान-प्रदान का करार हुआ और 31 जुलाई, 2015 को समझौता अमल में आया।**

समझौते से फायदे

- **लोगों को एक देश की नागरिकता मिल जायेगी।**
- **अब सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा।**
- **बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी।**
- **नवंबर, 2015 से निर्बाध रूप से आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।**

राजनीतिक दलों के लिये आचार-संहिता

✍ पं. दीनदयाल उपाध्याय

व्यक्ति का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता जनतन्त्र का मूलभूत सिद्धान्त है। इन्हें नष्ट करने वाला किसी भी दल का आदर्श अजनतांत्रिक होगा।

जबकि एक ओर समाज के लिये व्यक्तिगत स्वातंष्य की प्रत्याभूति (गारंटी) और रक्षा आवश्यक है, व्यक्ति के लिये सर्वसामान्य की इच्छा का स्वेच्छया समादर करना भी वांछनीय है। यह सहिष्णु भावना जितनी अधिक होगी, राज्य के अदम्य अधिकार उतने ही कम हो जायेंगे।

जनता में विधान के प्रति समादर की भावना उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है कि विधान का संरक्षक बनने की आकांक्षा रखने वाले दल इस दिशा में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें।

किसी दल में, जिसके कार्यों का किसी सरकारी विधान द्वारा नियमन नहीं होता, प्रत्युत् वे दल की इकाइयों द्वारा स्वेच्छया स्वीकृत निर्णयों के अनुसार चलते हैं, इसके उदाहरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए कि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का सर्वोत्तम सन्तुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। अतः दलों के लिये यह आवश्यक है कि वे अपने सदस्यों के लिये एक आचरण-संहिता निर्धारित करें और उसका कड़ाई से पालन करें। स्वशासन की भावना और क्षमता जनतन्त्र का सार है।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को अपने लिये एक दर्शन (सिद्धान्त या आदर्श) का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिये एकत्र होने वाले लोगों का समुच्चय मात्र नहीं बनना चाहिए। अपने पास (दल में) आने वाले लोगों के दृष्टिकोणों की कोई चिन्ता न करके केवल अनुयायियों की संख्या बढ़ाना अनुचित है। राजनीतिक दल को व्यापारिक प्रतिष्ठान (जौइन्ट स्टाक कम्पनी) से भिन्न होना चाहिए। राजनीतिक सत्ता पर निश्चित सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ध्यान देना उचित है न कि सत्ता की होड़ के लिये। राजनीति साधन है, साध्य नहीं।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को अपने लिये एक दर्शन (सिद्धान्त या आदर्श) का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिये एकत्र होने वाले लोगों का समुच्चय मात्र नहीं बनना चाहिए। अपने पास (दल में) आने वाले लोगों के दृष्टिकोणों की कोई चिन्ता न करके केवल अनुयायियों की संख्या बढ़ाना अनुचित है।

जनतन्त्र में सत्ता के प्रति उच्च स्तर की निरासक्ति आवश्यक है। भगवान राम की तरह, जनतन्त्र में राजनीतिज्ञ को आवाहन मिलने पर सत्ता स्वीकार करने और क्षति की चिन्ता किये बिना उसका परित्याग कर देने के लिये भी सदा तैयार रहना चाहिए। खिलाड़ी की तरह उसे विजय के लिये संघर्ष करना चाहिए, किन्तु पराजय के लिये भी तैयार रहना चाहिए।

हर व्यक्ति तब तक जनतन्त्रवादी होने का स्वांग कर सकता है, जब तक उसे जन-समर्थन प्राप्त है, किन्तु जनतंत्रवादी बने रहने के लिये उस समय गहरी आस्था की आवश्यकता होती है, जब आप हार जायँ।

दो आम चुनावों के बीच केवल छोटे प्रश्नों के लिये सरकार पर दबाव डालना चाहिए और बड़े प्रश्नों को जनता के निर्णय के लिये छोड़ देना चाहिए। चुनाव में सरकार को बदल देने के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से सरकारी नीति में बड़े परिवर्तन के लिये दबाव डालना अप्रजातान्त्रिक होगा।

सरकार को प्रस्तावों और आवेदनों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनना चाहिए। विरोधियों एवं आन्दोलनकारियों की बातों से सहमत होते हुए भी, शासक उन्हें कार्यान्वित करने के लिये यदि केवल इसलिये तैयार न हों कि इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा की हानि होगी तथा विरोधियों का मूल्य बढ़ेगा, तो यह अनुचित है। रचनात्मक कार्य का सुदृढ़ आधार होने पर किसी प्रकार की झूठी प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा नहीं होता।

देश का शासन सरकार के माध्यम से संसद द्वारा किया जाता है, अतः विरोधी दल संसद द्वारा उत्तरदायित्वों के निर्वाह में योगदान करता है, अन्यथा राष्ट्रद्रोह और विरोधी दल में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा।

संसदीय पद्धति का अर्थ है- विचार-विमर्श के आधार पर चलने

वाली सरकार, और उस पद्धति में अधिकारारूढ़ व्यक्तियों को विरोधियों के दृष्टिकोण पर विचार करने तथा उसे मान्य करने के लिये सदैव तैयार रहना होता है।

सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य है कि वह विरोधी दल के विचारों का आदर कर समन्वय की भावना से शासन करे। सामंजस्य और समन्वय की इस भावना के लिये सहिष्णुता की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि जनतंत्र की भागीरथी का अटूट स्रोत सहिष्णुता ही है। भारतीय संस्कृति का आधार ही सहिष्णुता है। जनतन्त्र में सरकार विरोधी दल को सहन ही नहीं करती, अपितु उसका विश्वास भी करती है।

सत्तारूढ़ लोगों के मन में जनतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी दल पर प्रतिबन्ध लगाने के विचारों का उदय होना भी जनतंत्र में एक पाप है।

चाहे जैसा आदर्श किसी दल को जनतन्त्र का युग लाने में समर्थ नहीं बनायेगा। वह आदर्श स्वयं जनतन्त्र के आदर्शों और भावनाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए।

सैद्धान्तिक आधार पर किसी दल से सम्बन्ध-विच्छेद को उचित माना जा सकता है, किन्तु अन्य आधारों पर दलों को दल-बदल को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में, जब कोई दल बहुमत में न आये, या उसे अत्यल्प बहुमत प्राप्त हो, तब अन्य दलों से समर्थन पाने के लिये राजनीतिज्ञों द्वारा अनुचित साधन अपनाये जाने की संभावना होती है। यह आवश्यक है कि हम ब्रिटेन की दो दलीय संसदीय पद्धति से कुछ अलग परंपराएं विकसित करें और अपनायें। केवल उससे ही देश में स्थिर सरकार रहेगी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बनने से दलों की रक्षा हो सकेगी।

राष्ट्र एक है, राष्ट्रजन एक हैं, अतः राजनीति में (अर्थात्- राजनीतिक दलों के द्वारा) किसी विशेष सम्प्रदाय, किसी विशेष भाषा-भाषी समूह, किसी विशेष प्रान्त या क्षेत्र अथवा किसी अर्थिक या सामाजिक वर्ग का विचार इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि वह राष्ट्र का सामान्य अवयव न प्रतीत होकर एक पृथक इकाई जान पड़े।

किसी दल में संगठन-पक्ष और विधायक-पक्ष का संतुलन व्यावहारिक आधार पर होना चाहिए। सिद्धान्ततः जनतन्त्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है और उसके प्रतिनिधियों को उनकी अपनी अंतश्चेतना, जनमत और संविधान के अतिरिक्त अन्य किसी का नियंत्रण नहीं मान्य करना चाहिए। किन्तु व्यवहार में, दलीय पद्धति के जनतंत्र में दल के समर्थन के आधार पर ही प्रत्याशी निर्वाचित होता है। बहुधा जनता किसी दल के व्यक्ति की अपेक्षा दल का समर्थन करती है। व्यक्ति भी अपनी स्वयं की इच्छा से दल का अनुशासन स्वीकार कर लेता है। इसलिये वह केवल उस समय जनता के नाम की दुहाई नहीं दे सकता, जब दल के निर्देश का पालन करना उसके लिये असुविधाजनक बन जाय। विशेषतः एक ऐसी पद्धति में, जिसमें प्रतिनिधि को वापस बुला लेने की व्यवस्था नहीं है, चुनाव के बाद दल ही विधायक के आचरण को नियमित रख सकता है। अगला चुनाव होने तक जनता तो निरुपाय रह जाती है।

दलीय अनुशासन दल की सुस्थिति ही नहीं, अपितु दलगत आधार पर शासन-व्यवस्था के लिये भी आवश्यक है। किन्तु, जब अनुशासन चीनी स्त्रियों के जूते के समान बुरी तरह से जकड़ ले तो उसमें व्यक्ति तथा दल या देश-दोनों का विकास रुक जाता है। जनतन्त्र कम से कम वहां पनप नहीं सकता। प्रवर समिति की बैठकों तक में दल के सचेतक द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करना उचित नहीं है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक है।

सत्तारूढ़ दल द्वारा दल के नेता को ही विधायिका का नेता बना देने से देश में दल की तानाशाही चलने लगेगी।

राष्ट्र एक है, राष्ट्रजन एक हैं, अतः राजनीति में (अर्थात्- राजनीतिक दलों के द्वारा) किसी विशेष सम्प्रदाय, किसी विशेष भाषा-भाषी समूह, किसी विशेष प्रान्त या क्षेत्र अथवा किसी अर्थिक या सामाजिक वर्ग का विचार इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए कि वह राष्ट्र का सामान्य अवयव न प्रतीत होकर एक पृथक इकाई जान पड़े। प्रत्येक समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, न कि वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र या भाषा विशेष के दृष्टिकोण से; क्योंकि जैसे हमारा शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं है, वैसे ही राष्ट्र भी इन तथाकथित वर्गों या इकाइयों का केवल समूह नहीं, वरन् एक जीवन्त एकात्मक इकाई है।■

दीनदयाल शोध संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका 'मंथन' (जुलाई 1979) से साभार

श्रद्धांजलि

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम नहीं रहे

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का दिल का दौरा पड़ने से 27 जुलाई को शिलांग के एक अस्पताल में निधन हो गया। वर्ष 2002 से 2007 के दौरान राष्ट्रपति रहे 83 वर्षीय डॉ. कलाम 27 जुलाई की शाम करीब 6 बजकर 30 मिनट पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में लेक्चर देने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। इसके बाद उन्हें यहां के बेथानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'भारत रत्न' डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक नाविक के घर हुआ था। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर, 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 1963 में डॉ. कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो से जुड़े। इसके बाद वे सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल प्रॉजेक्ट मिशन से जुड़े।

डॉ. कलाम ने अपनी मेहनत और बुद्धिमता से न सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की, बल्कि भारत के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। डॉ. कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और 'भारत रत्न' एपीजे अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे।

डॉ. कलाम के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि एक महान वैज्ञानिक, उत्तम राष्ट्रपति और इन सबसे ऊपर एक प्रेरणादायक व्यक्ति के निधन से देश शोकाकुल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य, उनका जीवन, उनकी हर बात देश के लिए

आज भी दिशादर्शक है। एक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भारत को नयीं ऊंचाईयों पर पहुँचाया। भारत को सशक्त बनाने में, वैज्ञानिक शक्ति को जोड़ने का उनका जीवन भर का प्रयास भारत की बहुत बड़ी पूँजी है।

श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति थे तब भी और बाद में भी यही कहते थे कि मैं तो एक टीचर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ। पढ़ाना मेरा पैशन है। और आज जीवन का अंत काल भी विद्यार्थियों के बीच, अपने प्रिय काम को करते-करते ही उन्होंने वो अंतिम क्षण भी बितायी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत मेरे जीवन में एक उत्तम, वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे थे। उनके साथ बहुत निकटता से काम करने का मुझे अवसर मिला था। मैंने व्यक्तिगत जीवन में तो एक उत्तम मार्गदर्शक को खोया है, देश ने अपने एक ऐसे सपूत को खोया है, जिसने भारत की सेवा की, भारत को सशक्त बनाने के लिए। जिसने अपनी पल-पल लगायी, भारत की युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए। ऐसे महापुरुष की विदाई, मैं नहीं मानता कि कोई भर पायेगा। देश ने बहुत कुछ आज गंवाया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी पूर्व राष्ट्रपति डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के निधन पर शोक जताया। 28 जुलाई की सुबह मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में एक

शेष पृष्ठ 18 पर

भाजपा अध्यक्ष का शोक संदेश

पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम के निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ है। एक सच्चे देशभक्त, महान वैज्ञानिक, भविष्यदृष्टा और कर्मयोगी डा. कलाम ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण को समर्पित किया। मिसाइलमैन के नाम से विख्यात डा. कलाम का जीवन सदैव सादगी भरा रहा, वो विज्ञान, शिक्षा और नैतिकता के एक दुर्लभ संयोजन थे। डा. कलाम ने एक विकसित, संपन्न व शक्तिशाली भारत का सपना संजोया और सदैव ही उसे साकार करने को समर्पित रहे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष और परमाणु महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डा. कलाम के योगदान के लिए राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। उनके निधन से राष्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है। श्री कलाम का व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा।■

भारत ने एक हीरा खो दिया है

✍ नरेन्द्र मोदी

ए पीजे अब्दुल कलाम के रूप में भारत ने एक हीरा खो दिया है। लेकिन उस हीरे की चमक और रोशनी हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगी, जो उस स्वप्नद्रष्टा ने देखी थी। उन्होंने ख्वाब देखा था कि भारत एक नॉलेज सुपरपावर (ज्ञान शक्तिपुंज) के रूप में पहली कतार के देशों में शुमार हो।

हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से चलकर राष्ट्रपति पद तक पहुंचे कलाम सच्चे मायनों में जनता के राष्ट्रपति थे और यही कारण था कि उन्हें जनता से अथाह प्यार और सम्मान मिला और शायद उनके लिए सफलता का अर्थ भी यही था।

उनकी हर कथनी-करनी में इसी की झलक मिली। गरीबी से लड़ने का उनका हथियार था ज्ञान और इसे फैलाने में उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा कार्यक्रम के वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने क्षितिज को पार किया तो एक सच्चे संत के रूप में उन्होंने बताया कि सद्भाव का आकाश सबसे बड़ा है।

हर बड़ी शख्सियत का जीवन एक प्रिज्म की तरह होता है। रोशनी उससे होकर गुजरती है तो हम पर सतरंगी किरणों की वर्षा होती है। कलाम का आदर्शवाद यथार्थ के आधार पर टिका था। सही मायनों में हर वंचित बच्चा यथार्थवादी होता है। गरीबी से भ्रम पैदा नहीं होता है।

गरीबी एक ऐसी डरावनी विरासत है जिसके बोझ तले बच्चा सपना भी नहीं देख सकता है। वह उससे पहले ही

पूर्व राष्ट्रपति कलाम हम सभी के मार्गदर्शक थे जो हमारी सभ्यता के तीनों गुण, दम (आत्म-नियंत्रण), दान और दया से परिपूर्ण थे।

देश के लिए राष्ट्रपति कलाम का विजन स्वतंत्रता, विकास और शक्ति के तीन स्तंभों से प्रेरित था।

डॉ. कलाम का व्यक्तित्व एक बच्चे की ईमानदारी, युवा होते एक बच्चे का उत्साह और एक वयस्क की परिपक्वता का सम्मिश्रण।

परास्त हो जाता है। लेकिन कलाम जी को परिस्थितियों से हार मानना स्वीकार नहीं था। उनका बचपन भी कठिन था। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने अखबार भी बेचा। आज सभी अखबार उनकी याद और श्रद्धांजलि से पटे पड़े हैं।

उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनका जीवन दूसरों के लिए रोल माडल है, लेकिन यह सच्चाई है कि उनसे प्रेरणा लेकर गरीबी और अंधकार से भ्रमित और ग्रसित किसी असहाय बच्चे को बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। कलाम मेरे मार्गदर्शक हैं। उसी तरह जैसे हर बच्चे के।

उनका आचरण, समर्पण और उनकी प्रेरणादायी सोच उनके पूरे जीवन से प्रस्फुटित होती है। अहं उन पर कभी हावी नहीं हो सका और चापलूसी कभी रास नहीं आई। हाई प्रोफाइल मंत्री हों या उच्च सामाजिक वर्ग के श्रोता या फिर युवा छात्र, उन पर इसका कभी कोई फर्क नहीं दिखा।

वह हर किसी के लिए एक समान थे। उनके व्यक्तित्व में अदभुत बात थी- वह था एक छोटे बच्चे की ईमानदारी, युवा होते एक बच्चे का उत्साह और एक वयस्क की परिपक्वता का मिश्रण। यह हर क्षण उनके व्यक्तित्व में झलकता था। संसार से उन्होंने जो कुछ लिया वह पूरा समाज पर लुटा दिया। गहरी आस्था रखने वाले कलाम हमारी सभ्यता के तीनों गुण - दम(आत्म नियंत्रण), दान और दया से भरपूर थे।

लेकिन इस व्यक्तित्व में प्रयत्नशीलता की आग थी। राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि का निर्माण स्वतंत्रता, विकास और शक्ति के तीन स्तंभों पर हुआ था। हमारे इतिहास में स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता से है। परंतु इसमें वैचारिक व बौद्धिक स्वतंत्रता भी शामिल है। वह भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र के रूप में

परिवर्तित होते और समवेत आर्थिक विकास के जरिये गरीबी को समाप्त करना चाहते थे।

इसीलिए उन्होंने कहा था कि नेताओं को केवल 30 फीसद समय राजनीति में और 70 फीसद विकास में लगाना चाहिए। वह अक्सर सांसदों को बुलाकर उनके साथ उनके क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर चर्चा किया करते रहते थे।

उनके मुताबिक, राष्ट्र की शक्ति का तीसरा स्तंभ यानी क्षमता केवल आक्रामकता से नहीं, बल्कि समझ विकसित करने से मजबूत होता है। एक असुरक्षित राष्ट्र शायद ही कभी समृद्धि के रास्ते पर जा सकता है। शक्ति से सम्मान प्राप्त होता है। हमारी नाभिकीय एवं अंतरिक्ष संबंधी उपलब्धियों में उनके योगदान ने ही भारत के अंदर विश्व में उचित स्थान पाने की शक्ति व भरोसा पैदा किया है। हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं खड़ी कर उनकी याद को सम्मान दे सकते हैं जो विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा देती हों और प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करने में हमारी मदद करें। अक्सर हम लालच के वशीभूत होकर प्रकृति का शोषण करने लगते हैं। लेकिन कलाम जी को पेड़ों में कविता, जबकि पानी, हवा और सूरज में ऊर्जा दिखाई देती थी। हमें अपनी दुनिया को उनकी आंखों और उन्हीं के जैसे उत्साह से देखने का अभ्यास करना होगा।

मनुष्य अपने जीवन को अपनी इच्छा, संकल्प, क्षमता और साहस के अनुसार संचालित कर सकता है। परंतु उसे अपने जन्म का स्थान और मृत्यु का समय तय करने का अधिकार नहीं मिला है। परंतु यदि कलाम जी को यह अधिकार मिलता तो अवश्य ही वह कक्षा में अपने प्रिय छात्रों को पढ़ाते हुए संसार से रुखसत होना पसंद करते। यदि कोई कहता है कि अविवाहित होने के नाते उनके कोई संतान नहीं थी, तो यह सही नहीं होगा।

वस्तुत: वह प्रत्येक भारतीय बच्चे के पिता थे। जिन्हें वह न केवल पढ़ाते और मनाते थे, बल्कि उनका जोश बढ़ाते थे और अपनी दृष्टि की आभा और स्नेह से उनके भीतर से अज्ञान के अंधेरे को दूर करते थे। उन्होंने खुद भविष्य को देखा और दूसरों को रास्ता दिखाया।

मैने जब उस कमरे में प्रवेश किया, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था तो मेरी नजर द्वार के पास लटकी एक पेंटिंग पर पड़ी। उस पर कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स की कुछ प्रेरणादायी पंक्तियां लिखी थीं। उनका काम उनके साथ समाप्त नहीं होगा। यह अनंत के लिए है। उनकी प्रेरणा बच्चों के जीवन और काम को दिशा दिखाएगी और फिर आगे उनके बच्चों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगी। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं।)

हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं खड़ी कर उनकी याद को सम्मान दे सकते हैं जो विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा देती हों और प्रकृति की आश्चर्यजनक शक्ति के साथ तादात्म्य स्थापित करने में हमारी मदद करें। अक्सर हम लालच के वशीभूत होकर प्रकृति का शोषण करने लगते हैं। लेकिन कलाम जी को पेड़ों में कविता, जबकि पानी, हवा और सूरज में ऊर्जा दिखाई देती थी। हमें अपनी दुनिया को उनकी आंखों और उन्हीं के जैसे उत्साह से देखने का अभ्यास करना होगा।

पृष्ठ 16 का शेष...

प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि कि उनके निधन से देश ने एक दूरदृष्टा वैज्ञानिक, एक सच्चा राष्ट्रवादी और महान सपूत खो दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार और पूरे देश की ओर से शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदनाएं भेजी गई।

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है, वह कभी भरा नहीं जा सकता। श्री आडवाणी ने कहा कि वर्ष 2020 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने के उनके विश्वास ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। वह जीवन भर एक शिष्य और शिक्षक रहे। युवा मस्तिष्कों को प्रोत्साहित करने की क्षमता के मामले में भी वह बेमिसाल थे। उन्होंने कहा कि कलाम के निधन से हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढियां उन्हें बेहद प्यार के साथ एक आदर्श भारतीय के रूप में याद करती रहेगी। ■

असहमति या व्यवधान – जीएसटी पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति

– अरुण जेटली

राज्यसभा में माल और सेवा कर पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। संविधान संशोधन विधेयक को पहले से ही लोक सभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रवर समिति ने उन राज्यों के लिए एक पांच साल की मुआवजे की सिफारिश की है, जिन्हें जीएसटी के कारण किसी भी तरह के राजस्व का नुकसान हुआ है।

इतिहास

जीएसटी की शुरूआत का प्रस्ताव सबसे पहले श्री पी चिदंबरम ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में दिया था। राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति से विस्तृत विचार-विमर्श और बातचीत के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 115वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया जिसने अगस्त 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, हालांकि यह विधेयक पंद्रहवीं लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया।

इसके बाद राजग सरकार ने फिर से अधिकार प्राप्त समिति के साथ वार्ता की और एक जबरदस्त आम सहमति के बाद इस विधेयक को कुछ परिवर्तनों के साथ पेश किया जिस बदलाव की संसदीय स्थायी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। अधिकार प्राप्त समिति जोकि पूर्ण रूप से कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा समर्थित थे, के लगभग सभी सुझावों को सूचीबद्ध करते हुए संविधान में संशोधन करने के लिए समापक विधेयक तैयार किया गया जिसे मेरे द्वारा 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया।

औचित्य

विधेयक का औचित्य देश में जटिल अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है।

विधेयक का औचित्य देश में जटिल अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल बनाना है। वर्तमान व्यवस्था में करों की बहुलता, कराधान की समरूप दरों का अभाव और 'टैक्स के ऊपर टैक्स' का व्यापक प्रभाव शामिल है। यह भी देश भर में माल और सेवाओं की निर्बाध हस्तांतरण में एक बाधा है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाता है। इसका मुख्य काम उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, करों की बहुलता और असमान कराधान को कम करना है। गौरतलब है कि इससे देश भर में माल और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण होता है और लेन-देन की लागत में भी कटौती होती है।

वर्तमान व्यवस्था में करों की बहुलता, कराधान की समरूप दरों का अभाव और 'टैक्स के ऊपर टैक्स' का व्यापक प्रभाव शामिल है। यह भी देश भर में माल और सेवाओं की निर्बाध हस्तांतरण में एक बाधा है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाता है। इसका मुख्य काम उत्पादन लागत, मुद्रास्फीति, करों की बहुलता और असमान कराधान को कम करना है। गौरतलब है कि इससे देश भर में माल और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण होता है और लेन-देन की लागत में भी कटौती होती है।

यह कर आधार को व्यापक बनाएगा, बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होंगे और अंततः देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी। बेहतर कर अनुपालन के परिणामस्वरूप जीएसटी राज्यों के राजस्व में सुधार करेगी और निश्चित रूप से देश के कम विकसित राज्यों में से अधिकांश के साथ न्याय करेगी। यही कारण है कि अधिकतम राज्य और क्षेत्रीय दल जीएसटी के समर्थक हैं।

कांग्रेस की असहमति

कांग्रेस पार्टी के तीन सदस्यों ने असहमति की एक प्रति प्रसारित की है जो प्रवर समिति की एक आम सहमति की रिपोर्ट के विपरीत है। मैं असहमति के अपने नोट में कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए बिंदुओं में से प्रत्येक पर टिप्पणी

करना चाहता हूँ।

(1) कांग्रेस के सदस्यों ने प्रस्ताव दिया है कि जीएसटी की दर संविधान में 18 प्रतिशत से अधिक नहीं के रूप में तय हो। यह सुझाव श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित विधेयक में नहीं था। जब श्री पी. चिदंबरम ने अधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत की तो उसमे भी यह सुझाव मौजूद नहीं था। कराधान की दर आम तौर पर संविधान में तय नहीं होते तब जबकि हम एक गतिशील और परिवर्तनशील दुनिया में रहते हों। दरों को जीएसटी समिति द्वारा सिफारिश किया जाना है जो आर्थिक स्थिति, राजस्व में उछाल आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी की दरों की सिफारिश में कुछ तर्क हो सकता है। हालांकि, यह निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाना है और यह संविधान का एक हिस्सा नहीं हो सकता। जीएसटी दर मेजबान के कारकों के आधार पर निर्भर करेंगे और उसी हिसाब से तय होंगे।

(2) कांग्रेस ने आगे प्रस्तावित किया है कि अभिव्यक्ति 'आपूर्ति' एक कंपनी के एक इकाई से उसी कंपनी की दूसरी इकाई को आपूर्ति की गयी वस्तुओं और सेवाओं के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह का कोई प्रस्ताव न तो श्री प्रणव मुखर्जी के विधेयक में था और न ही श्री चिदंबरम द्वारा मंजूर किये गए प्रस्ताव में। हालांकि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया जीएसटी वैट की श्रेणी में आएगा और इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं है।

(3) कांग्रेस का प्रस्ताव है कि राजस्व उछाल में स्थानीय निकायों का प्रस्तावित संविधान संशोधन में एक हिस्सा होना चाहिए। यह संविधान के 73वें संशोधन के विपरीत जाता है जो राज्य वित्त आयोग की स्थापना के लिए प्रदान की जाती है और ऐसी सिफारिशों की जिम्मेदारी उनकी है। हालांकि न ही श्री प्रणव मुखर्जी ने और न ही श्री चिदंबरम ने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार किया था।

कांग्रेस ने आगे प्रस्ताव दिया है कि जीएसटी परिषद में राज्यों के मतदान प्रतिनिधित्व को जो दो-तिहाई पर रखा गया है उसे बढ़ाकर तीन-चौथाई की जानी चाहिए। यह प्रभावी रूप से केंद्र के मतदान शक्ति को एक तिहाई से घटाकर एक-चौथाई पर सीमित कर देगा। यह श्री चिदंबरम के 30 अप्रैल 2013 के विशेष रूप से लिए गए निर्णय के विपरीत है। वास्तव में, कांग्रेस के प्रस्ताव का यह मतलब होगा कि यदि सभी राज्य एक साथ मिलकर यह निर्णय ले लें कि केंद्र की जीएसटी दर कम होनी चाहिए तो वे केंद्र के राजस्व को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भारत राज्यों का एक संघ है। क्या कांग्रेस का यह प्रस्ताव है कि संघ आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहे?

(4) कांग्रेस ने अगला प्रस्ताव दिया है कि ऐसे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए चाहे उनके पास विधायिका हो या न हो तथा जिनकी जनसंख्या बीस लाख से अधिक नहीं हो। श्री प्रणव मुखर्जी या श्री चिदंबरम का ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं था। हालाँकि, विशेष श्रेणी के अनुमोदन के लिए प्रावधान कारकों में से एक मेजबान पर आधारित है। कांग्रेस गोवा को जीएसटी के तहत एक विशेष श्रेणी का राज्य बनाना चाहती है, लेकिन गोवा की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है।

(5) कांग्रेस का अगला प्रस्ताव है कि संशोधन विधेयक में पेट्रोलियम की ही तरह मानव उपभोग की चीजों बिजली, तम्बाकू उत्पादों और शराब को भी भाव मिलना चाहिए। कांग्रेस के किसी भी वित्त मंत्री ने यह प्रस्ताव नहीं रखा था। अगर कांग्रेस के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया तो राज्यों के साथ एक आम सहमति बुरी तरह से बिखर जाएगी। पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल किया गया है लेकिन जीएसटी किसी उत्पाद पर तभी लगाया जायेगा और इस पर तभी शुल्क लिया जाएगा जब समिति इस पर कोई निर्णय लेती है।

(6) कांग्रेस ने आगे प्रस्ताव दिया है कि जीएसटी परिषद में राज्यों के मतदान प्रतिनिधित्व को जो दो-तिहाई पर रखा गया है उसे बढ़ाकर तीन-चौथाई की जानी चाहिए। यह प्रभावी रूप से केंद्र के मतदान शक्ति को एक तिहाई से घटाकर एक-चौथाई पर सीमित कर देगा। यह श्री चिदंबरम के 30 अप्रैल 2013 के विशेष रूप से लिए गए निर्णय के विपरीत है। वास्तव में, कांग्रेस के प्रस्ताव का यह मतलब होगा कि यदि सभी राज्य एक साथ मिलकर यह निर्णय ले लें कि केंद्र की जीएसटी दर कम होनी चाहिए तो वे केंद्र के राजस्व को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भारत राज्यों का एक संघ है। क्या कांग्रेस का यह प्रस्ताव है कि संघ

आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहे? क्या उनका यह प्रस्ताव है कि केंद्र को राष्ट्रीय कराधान की व्यवस्था में कोई दखल नहीं देना चाहिए? लगता है कि कांग्रेस ने बिना पर्याप्त दिमाग लगाये हुए इस प्रस्ताव का यह संशोधन मसौदा तैयार किया है।

(7) कांग्रेस ने आगे प्रस्ताव दिया है कि जीएसटी से सम्बंधित किसी भी विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई जीएसटी ट्रिब्यूनल द्वारा होना चाहिए। विवादों के निपटारे और अधिनिर्णय के तौर-तरीकों को तय करने की शक्ति वर्तमान विधेयक में जीएसटी समिति के पास है। राजनीतिक मुद्दों का समाधान राजनीतिक तौर पर ही किया जाना चाहिए, न्यायाधीशों द्वारा नहीं। जीएसटी के मूल प्रस्ताव में उल्लेखित विवाद निवारण ट्रिब्यूनल के गठन को स्थायी समिति और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यूपीए सरकार ने स्थायी समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। यह एक बाद का सुझाव है जो केवल कांग्रेस के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए चुना गया है।

राजनीतिक मुद्दों का समाधान राजनीतिक तौर पर ही किया जाना चाहिए, न्यायाधीशों द्वारा नहीं। जीएसटी के मूल प्रस्ताव में उल्लेखित विवाद निवारण ट्रिब्यूनल के गठन को स्थायी समिति और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यूपीए सरकार ने स्थायी समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया था। यह एक बाद का सुझाव है जो केवल कांग्रेस के प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए चुना गया है।

(8) कांग्रेस पार्टी ने निर्यात करने वाले राज्य को 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर का क्रेडिट दिए जाने के दो साल के क्षणिक प्रावधान का विलोपन करने के लिए कहा है। यह प्रावधान कुछ उत्पादक राज्यों के डर को दूर करने के क्रम में जोड़ा गया है जिन्हें यह महसूस हो रहा था कि उन्हें आरम्भ में राजस्व का नुकसान होगा। यह अधिकार प्राप्त समिति के एक सर्वसम्मत निर्णय पर आधारित है जिस पर कांग्रेस शासित सभी राज्य सहमत हैं।

यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी जिसने 2006-07 के बजट में जीएसटी का प्रस्ताव किया था। संविधान संशोधन यूपीए सरकार द्वारा संचालित किया गया था। अधिकार प्राप्त समिति और स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को यूपीए सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच एक आम सहमति बनाने को छोड़कर वर्तमान सरकार ने कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित राज्य सरकारों ने लगातार प्रस्ताव का समर्थन किया है। क्या यह केवल बाधा डालने का रवैया इख्तियार करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने एक एक नकारात्मक भूमिका अपनाई है? चूंकि कांग्रेस के इन्हीं नकारात्मक राजनीति के कारण संसद में कार्य नहीं हो रहा है और इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया है, इसलिए मैं उपरोक्त तथ्यों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से इसे सार्वजनिक करने को विवश हूँ।

कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राजनीतिक कारणों के लिए सरकार से परेशान हो सकते हैं। वे 2014 के फैसले के लिए मतदाताओं से परेशान हो सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए और गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहिए कि नकारात्मकता से देश को नुकसान होता है। क्या इनकी इसी नकारात्मक और विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने की प्रवृत्तियों ने देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल किया है और अर्थव्यवस्था को एक चोट पहुंचाई है?

कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राजनीतिक कारणों के लिए सरकार से परेशान हो सकते हैं। वे 2014 के फैसले के लिए मतदाताओं से परेशान हो सकते हैं। देश में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार करना चाहिए और गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहिए कि नकारात्मकता से देश को नुकसान होता है। क्या इनकी इसी नकारात्मक और विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने की प्रवृत्तियों ने देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल किया है और अर्थव्यवस्था को एक चोट पहुंचाई है? ■

(लेखक केंद्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

भारत सरकार और नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर

नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन-इसाक मुइवा) और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौता होना पूर्वोत्तर के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी है। ऐसा कर नगा अलगाववादियों के एक बड़े गुट को केंद्र सरकार ने मुख्य धारा में ला दिया है। इससे देश की सबसे पुरानी अलगाववादी समस्या खत्म होगी ही, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में मजबूती आने से सीमावर्ती इलाके पर भारत की पकड़ भी मजबूत होगी। इस समझौते से पूर्वोत्तर, खासकर, नागालैंड के लोगों का भी भला होगा।

भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) ने छः दशकों से मौजूद नगाओं की राजनीतिक समस्याओं पर आधारित वार्ता का सफल समापन करते हुए 3 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत सरकार की ओर से नगा शांति वार्ताओं के लिए नियुक्त सरकार के मध्यस्थ श्री आर एन रवि ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। एनएससीएन की ओर से अध्यक्ष श्री इसाक चीसी स्वू और महासचिव श्री थ. मुईवा ने हस्ताक्षर किए। एनएससीएन (आईएम) के सामूहिक नेतृत्व से जुड़े सभी सदस्यों सहित पूरे शीर्ष नेतृत्व ने इस समझौते पर पूरी सहमति व्यक्त की और इस आयोजन में वे उपस्थित थे।

इस समझौते से देश में मौजूद सबसे पुरानी हिंसक गतिविधि समाप्त हो जाएगी। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे उनका जीवन सम्मानित होगा और नगाओं की बेजोड़ मेधाविता तथा उनकी संस्कृति और परम्पराओं के आधार पर उन्हें समान अवसर और समानता आधारित आजीविका मिलेगी।

खुद प्रधानमंत्री ने समझौते से ठीक पहले एक ट्वीट कर देश को जानकारी दी कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होने वाली घटना होने जा रही है। पीएम के इस ट्वीट ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सब कयास लगाने लगे कि आखिर पीएम मोदी कौन सी खास घोषणा करने वाले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का समझौता इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि हम समानता, सम्मान और विश्वास की भावना के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हुए क्या हासिल कर सकते

हैं, यह इस बात का उदाहरण है कि जब हम चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं और आकांक्षाओं पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, जब हम विवाद का मार्ग छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाते हैं। यह हमारी समस्याग्रस्त दुनिया में एक सबक और एक प्रेरणा की बात है।

गौरतलब है कि नगा लोगों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ताओं के माध्यम से समय-समय पर इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयास किए गए थे। वर्ष 1997 में एनएससीएन के साथ एक व्यापक समाधान की दिशा में एक ताजा प्रयास किया गया था। मई 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने पर इसने इस लंबित समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने दौरे के समय के साथ-साथ कई अन्य अवसरों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अपना दृष्टिकोण सामने रखा है और श्री मोदी ने इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, सम्पर्कता और आर्थिक विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार की विदेश नीति, विशेषकर एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में भी यह रहा है।

दोनों पक्षों के बीच जारी यह वार्ता समानता, आदर और विश्वास की भावना के साथ संचालित हुई और परस्पर समझ और आत्मविश्वास मजबूत होने के साथ-साथ दोनों पक्ष एक समानता आधारित समझौते तक पहुंचने में सक्षम हुए। भारत सरकार ने नगाओं के बेजोड़ इतिहास, उनकी संस्कृति और स्थिति के साथ ही उनकी संवेदनशीलताओं और आंकाक्षाओं को काफी महत्व दिया। एनएससीएन ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली और शासन को समझा और उसकी सराहना की।

नगा लोगों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ताओं के माध्यम से समय-समय पर इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रयास किए गए थे। वर्ष 1997 में एनएससीएन के साथ एक व्यापक समाधान की दिशा में एक ताजा प्रयास किया गया था। मई 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने पर इसने इस लंबित समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अपने दौरे के समय के साथ-साथ कई अन्य अवसरों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए अपना दृष्टिकोण सामने रखा है और श्री मोदी ने इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, सम्पर्कता और आर्थिक विकास को शीर्ष प्राथमिकता दी है। सरकार की विदेश नीति, विशेषकर एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में भी यह रहा है।

सरकारी मध्यस्थ ने भी नगाओं की पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं, नागरिक समाज, युवा और छात्रों की संस्थाओं, महिला समूहों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों सहित विभिन्न नगा नेताओं के साथ कई वार्ताएं की। इन वार्ताओं से नगा लोगों की आकांक्षाओं को जानने के साथ-साथ विश्वास और समझ का एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने में मदद मिली। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने नगा नेताओं और नागरिक समाज के साहस और बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए इस समझौते तक पहुंचने में उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

उन्होंने इस काम में सहयोग के लिए नगा लोगों की सराहना भी की और लगभग दो दशकों के लिए युद्ध विराम कायम रखने को लेकर एनएससीएन की भी सराहना की जिसके परिणामस्वरूप वार्ता सफल हुई। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुधार के लिए अपने दृष्टिकोण की चर्चा की। उन्होंने आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझौता नगालैंड के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में नगा लोगों के लिए एक शानदार नया अध्याय तैयार करेगा और राष्ट्र का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी योगदान करेगा।

एनएससीएन के महासचिव श्री थ. मुईवा ने नगाओं के संघर्ष के इतिहास की चर्चा की और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और संकल्प के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसके बल पर भारत सरकार और एनएससीएन का इस सम्मानजनक समझौते तक पहुंचना संभव हुआ। उल्लेखनीय है कि इस समझौता कार्यक्रम से सम्बन्धित विस्तृत विवरण और कार्यान्वयन योजना को जल्द जारी किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोवाल और भारत सरकार के अन्य शीर्ष गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एनएससीएन के पूरे सामूहिक नेतृत्व और विभिन्न नगा जनजातियों के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें अपना प्रतिनिधित्व किया।■

भारत सरकार और एनएससीएन के बीच समझौते पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी

'यह समस्या का अंत नहीं बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत है'

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, श्री मुइवाह एवं नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड के सभी वरिष्ठ नेता

इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी इच्छा थी कि इस समझौते को संभव बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री इसाक स्वू आज यहां उपस्थित होते। वह खराब स्वास्थ्य के कारण यहां उपस्थित नहीं हो सके। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिस प्रकार इस समझौते में उनका विशाल योगदान है, आगे आने वाले समय में उनका दिशानिर्देश महत्वपूर्ण बना रहेगा।

नगा राजनीतिक मुद्दा छह दशकों तक चलता आ रहा था जिसका हमारी पीढ़ियों पर काफी प्रतिकूल असर पड़ा। मैं तहेदिल से श्री इसाक स्वू, श्री मुइवाह एवं अन्य नगा नेताओं को उनकी बुद्धिमता और उनके साहस, उनके प्रयासों और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं जिसका परिणाम इस ऐतिहासिक समझौते के रूप में सामने आया है।

मेरे मन में नगा के महान लोगों के प्रति शांति प्रयासों के लिए उनके असाधारण सहयोग के कारण बेहद सम्मान है। मैं नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड को सम्मान की उस भावना के साथ, जो नगालैंड के महान लोगों को परिभाषित करती है, लगभग दो दशकों तक युद्धविराम समझौते को बनाये रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

पूर्वोत्तर के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा रहा है। मैंने कई अवसरों पर नगालैंड की यात्रा की है। मैं नगा लोगों के समृद्ध एवं विविध संस्कृति तथा जीने की अनोखी शैली से काफी प्रभावित रहा हूं। यह न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया को भी एक अधिक खूबसूरत जगह बनाती है। नगाओं का साहस और प्रतिबद्धता प्रसिद्ध रही है। इसके साथ-साथ, वे मानवता के उच्चतम स्तरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम प्रशासन एवं जमीनी स्तर के लोकतंत्र की उनकी प्रणाली शेष भारत के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए।

अशक्त और बुजुर्गों के लिए सम्मान, समाज में महिलाओं का दर्जा, प्रकृति माता के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक समानता पर जोर नगा जीवन का एक प्राकृतिक तरीका है। ये ही वे मूल्य हैं जो उस समाज की आधारशिला का निर्माण करते हैं जिसकी हम सभी कामना करते हैं। दुर्भाग्य से नगा समस्या ने समाधान के लिए काफी लंबा समय लिया क्योंकि हमने एक दूसरे को नहीं समझा। यह ब्रितानी शासन की विरासत है। औपनिवेशिक शासकों ने जानबूझकर नगाओं को अलग थलग और पृथक रखा। उन्होंने शेष भारत में नगाओं को लेकर भयंकर कल्पित कथाओं का प्रचार किया। उन्होंने जानबूझकर इस वास्तविकता को दबाये रखा कि नगा एक बेहद विकसित समाज हैं। उन्होंने शेष भारत में भी नगा लोगों के बीच नकारात्मक धारणाएं फैलाईं। यह औपनिवेशिक शासकों द्वारा बांटो और शासन करो की कुख्यात नीति का हिस्सा था।

यह स्वतंत्र भारत की एक त्रासदी है कि हम इस विरासत के साथ जी रहे हैं। महात्मा गांधी की तरह नगा लोगों को प्यार करने वाले तथा उनके प्रति संवेदी लोग बहुत अधिक संख्या में नहीं थे। हम एक दूसरे को गलत धारणाओं और पुराने पूर्वाग्रहों के आईना से देखते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि नगालैंड और शेष भारत का संपर्क कमजोर रहा। नगालैंड में आर्थिक विकास और प्रगति कम हुई और स्थाई शांति दूर रही।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री बनने के बाद से पूर्वोत्तर में शांति, सुरक्षा और आर्थिक बदलाव मेरी उच्च प्राथमिकताओं में रहा है। यह मेरी विदेश नीति विशेषकर लुक ईस्ट नीति के हृदय में है। मैं नगा

समस्या को सुलझाने के लिए गंभीर रूप से चिंतित हूं। मैंने पदभार ग्रहण करते ही नगा लोगों से बातचीत के लिए एक वार्ताकार की नियुक्ति की जिन्होंने न केवल नगा लोगों, उनकी आकांक्षाओं और आशाओं को समझा बल्कि लोगों के प्रति काफी लगाव और आदर है।

इस महत्व को देखते हुए मैंने अपने कार्यालय से बातचीत की देखरेख करने को कहा और मैंने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की प्रगति के बारे में संपर्क में रहा। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जिनका समर्थन और सलाह हमें यहां लाने में अमूल्य रहा। आज का समझौता इस बात का चमकता उदाहरण है कि हम एक दूसरे के साथ समानता, आदर और विश्वास की भावना से काम करके, चिंताओं को समझकर तथा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करके, विवाद का रास्ता छोड़कर और बातचीत का मार्ग अपना कर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। यह हमारे अशांत विश्व में शिक्षा और प्रेरणा का अध्याय है।

आज हम समस्या के अंत का नहीं बल्कि नए भविष्य की शुरुआत का प्रतीक मना रहे हैं। हम न केवल घाव को भरने और समस्याओं को हल करने का का काम करेंगे बल्कि आपके गौरव और सम्मान की स्थापना में सहयोगी होंगे। आज नगालैंड के नेताओं और जनता के लिए मैं कहता हूं: आप न केवल नगालैंड का चमकता भविष्य बनाएंगे बल्कि आपकी प्रतिभा, परंपरा और आपका प्रयास देश को मजबूत, अधिक सुरक्षित, अधिक समावेशी तथा समृद्ध बनाने में योगदान करेंगे। आप हमारी पूर्वी सीमा के अभिभावक हैं और विश्व के लिए मुख्य द्वार हैं।

समान रूप से बाकी देश नगा लोगों के लिए सम्मान, अवसर और समृद्धि के साथ भविष्य संवारने में शामिल होगा। आज आप गौरव, आत्म विश्वास और आत्म सम्मान के भाव से एक नया गौरवशाली अध्याय शुरु कर रहे हैं। मैं देश के साथ आपके नमन में शामिल होता हूं और नगा लोगों के लिए शुभ कामना व्यक्त करता हूं। ■

शांति समझौते का भाजपा ने किया स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का स्वागत किया है। श्री शाह ने छह दशक पुरानी नगाओं की राजनीतिक समस्याओं के सफल समाधान पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि नगा समस्या का सफल समाधान राजग सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि है। यह सफलता श्री मोदीजी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर है। श्री शाह ने कहा कि नगा समस्या के स्थाई समाधान से पूर्वोत्तर क्षेत्र में छह दशक पुरानी उग्रवाद की समस्या और हिंसक गतिविधियों का अंत होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापित होगी जिससे वहां निवेश और विकास का माहौल बनेगा तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे पूर्वोत्तर खासकर नगा समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई बार पूर्वोत्तर की यात्रा की है। यही वजह है कि पिछले साल मई में देश की बागडोर संभालने के बाद श्री मोदीजी ने नगाओं की राजनीतिक समस्या के स्थाई समाधान के प्रयास शुरु किए। यह विषय राजग सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति के केंद्र में भी रहा है।

श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। सीमा पार से गैर-कानूनी गतिविधियों के जरिए क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने वाली बाहरी शक्तियों के मंसूबे भी इससे नाकाम होंगे। इस तरह यह समझौता पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री शाह ने कहा कि राजग सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री मोदीजी के नेतृत्व में राजग सरकार भेदभावरहित सर्वसमावेशी विकास की नीति अपनाकर 'सबका साथ, सबका विकास' का संकल्प लेकर प्रगति पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार की यह उपलब्धि न सिर्फ पूर्वोत्तर के लिए बल्कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। श्री शाह ने इस ऐतिहासिक समझौते पर पूर्वोत्तर खासकर नगा समाज के लोगों को भी बधाई दी। श्री शाह ने कहा कि मेधावी नगा समाज की कर्मठता और पारस्परिक बंधुत्वों से पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से विकास पथ पर अग्रसर होगा। ■

परिवर्तन रैली, मुजफ्फरपुर (बिहार)

बिहार को जंगलराज, गुंडागर्दी और कुशासन से मुक्ति दिलायेंगे : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जुलाई को बिहार के मुजफरपुर में परिवर्तन रैली में उपस्थित विशाल जन-समूह को सम्बोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी नेताओं का नाम लेकर उन्हें सम्बोधित किया और रैली में उपस्थित विशाल जन समुदाय का आभार व्यक्त किया।

- **हम जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं, जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं।**
- **नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है।**
- **बिहार में भरपूर प्राकृतिक संसाधन और मानव बल है और इसे विकास से कोई नहीं रोक सकता।**
- **सांप और जहर के बयान से ज्यादा जरूरी बिहार का विकास है।**
- **आरजेडी पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगलराज का डर।**
- **बिहार को 2015-2020 वित्तीय वर्ष में विकास के लिए पौने चार लाख करोड़ रुपये दिए जायेंगे।**
- **बिहार को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।**
- **बरौनी की बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से शुरू किये जाने को स्वीकृति दे दी गयी है।**
- **रसोई गैस को बिहार के हर घर तक पहुँचाया जाएगा।**
- **बिहार को 50,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की आर्थिक मदद दी जाएगी।**
- **बिहार में निवेश पर 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी।**

उन्होंने अपने सम्बोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि मैंने तो इस विशाल हुजूम की कल्पना तक नहीं की थी। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा कि यदि सारे राजनीतिक विश्लेषक यह नजारा देख लें तो यह नतीजा साफ दिख जायेगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है।

श्री मोदी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा, 'जब मैं सोशल मीडिया पर ट्वीट करता था तो बिहार के एक नेता ताना मारा करते थे। वह कहते थे कि मोदी चहकते हैं। आज जब मैं बिहार आ रहा था तो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी आपका बिहार में स्वागत करता हूं। मैं उनके स्वागत करने पर आभार जताता हूं। एक वक्त था जब वह मुझे बिहार आने से रोकते थे। अब देखिए ट्वीट कर स्वागत कर रहे हैं। अपनों का विरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए किस कदर दुखी हैं। अब मैं आ गया हूं। अब आपको ज्यादा विरह नहीं झेलना पड़ेगा।'

उन्होंने लोगों को याद दिलाते हुए कहा कि पिछले दस साल में जो पीएम थे, वह यहां कभी नहीं आते थे, केवल हवाई सर्वेक्षण करते थे लेकिन नीतीश कुमार का मुझसे इतना लगाव है कि 14 महीनों की दूरी में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान हो गए।

उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि आपको बिहार में बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, जंगलराज से छुटकारा चाहिए, सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो आप हमें सेवा का एक मौका दें। मैं बिहार में सेवा करने का मौका मांगने आया हूं और मैं आप सब से यह वादा करता हूँ कि 60 महीनों में बिहार के लोगों के सपने को पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी निभाने

वाले लोग हैं और हम इसे पूरा करेंगें।

उन्होंने नीतीश के व्यवहार पर तंज कसते हुए कहा कि आपने एक व्यक्ति से नफरत के बदले पूरे बिहार के विकास का गला घोंट दिया है, क्या यही लोकतंत्र है? उन्होंने बड़े गंभीर लहजे में श्री नीतीश कुमार को इंगित करते हुए कहा कि मुझे इस बात का दु:ख नहीं है कि आपने मेरे साथ क्या किया, आपने भाजपा के साथ क्या किया, वरन दु:ख इस बात का है कि आपने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपने बिहार की जनता की आकांक्षाओं के साथ धोखा किया है।

उन्होंने कहा कि बिहार को फिर से जंगलराज और गुंडागर्दी के दलदल में हम नहीं भेज सकते, बिहार के लोगों को इस हाल में हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए इस बार का बिहार चुनाव युवाओं का भविष्य बदलने के लिए है, महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा की हमारी केंद्र सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा मंत्रालय का कार्यभार बिहार के नेताओं के जिम्मे दिया है, इसी से हमारी प्राथमिकता का पता चलता है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपने बिहार में विकास के कई मॉडल देखे, लेकिन एक बार एनडीए का विकास मॉडल आजमा कर जरूर देखिये।

नीतीश के सांप वाले बयान पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि सांप और जहर के बयान से ज्यादा जरूरी बिहार का विकास है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को पीने का साफ पानी चाहिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, यहाँ अच्छी सड़कों की जरूरत है, यहाँ उद्योग और कारखाने चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लालू के जहर पीने वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने तो स्वार्थवश सत्ता के लालच में जहर पिया था लेकिन आपने बिहार के लोगों को ये जहर पीने पर विवश क्यों किया, आपने बिहार के यदुवंशियों को जहर पीने पर मजबूर क्यों किया?

बिहार में देश की तकदीर बदलने की ताकत है, बिहार में संसाधन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की ये परेशानियां ज्यादा से ज्यादा सौ दिनों की हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता अब ज्यादा दिनों तक झेलने वाली नहीं है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार में देश की तकदीर बदलने की ताकत है, बिहार में संसाधन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की ये परेशानियां ज्यादा से ज्यादा सौ दिनों की हैं। श्री मोदी ने कहा कि बिहार की जनता अब ज्यादा दिनों तक झेलने वाली नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी को परिभाषित करते हुए कहा कि इसका पूरा अर्थ होता है 'रोजाना जंगलराज का डर।' उन्होंने बिहार की जनता से पूछा कि क्या बिहार की जनता को इस डर से मुक्ति चाहिए कि नहीं?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले बिहार में मेरी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी। श्री नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को खाने पर बुलाया था लेकिन उन्होंने थाली छीन ली। क्या कोई थाली परोसकर उसे वापस छीन लेता है? लालू जी, आपने तो जहर का पान अब किया मैंने तो पहले ही ये जहर पी लिया था। इनकी डीएनए में समस्या है। यह लोकतंत्र का डीएनए नहीं है। क्या यही लोकतंत्र का डीएनए है? जॉर्ज फर्नांडिस के साथ क्या किया गया? श्री सुशील मोदी के साथ इन्होंने क्या किया। जो व्यक्ति इनके साथ कंधा से कंधा मिलकर काम करता है, ये उन्हीं के पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज मैंने बिहार में हजारों-करोड़ों रुपये के कई योजनाओं का उद्घाटन किया। 2010 -2015 वित्तीय वर्ष के दौरान पिछली संप्रग सरकार ने बिहार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये दिए थे लेकिन हमारी सरकार ने 2015-2020 वित्तीय वर्ष में बिहार को पौने चार लाख करोड़ रुपया देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे बिहार के विकास में काफी मदद मिलेगी, उद्योग और कारखाने लगेंगे और बेहतर रोजगार सृजित होंगें।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के लिए उठाये गए प्रयासों पर रोशनी डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मैंने भूटान और नेपाल की यात्राएं की और जल-बिजली की दिशा में करार किया। उन्होंने कहा कि आज बिहार को 5000 मेगावाट बिजली की जरूरत है जबकि बिहार में केवल 300 मेगावॉट बिजली का उत्पादन है। उन्होंने कहा कि आज मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ

कि बिहार को 24 घंटे बिजली दी जाएगी।

प्रधानमंत्री ने बिहार में बरौनी की बंद फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह घोषणा की कि रसोई गैस को बिहार के हर घर तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम और लोगों की तरह केवल वादे नहीं करते, वरन हम चुनावों में किये गए वादों को याद भी रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने लोगों को पिछले लोक सभा चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि मैंने बिहार को 50,000 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने का वादा किया था, लेकिन मैंने यह निश्चय कर लिया है कि बिहार को इससे भी ज्यादा की आर्थिक मदद दी जाएगी और इसकी घोषणा मैं संसद के वर्तमान सत्र की समाप्ति पर फिर से बिहार आकर करूँगा।

उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारी एनडीए गठबंधन को आगामी विधान सभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से विजयी बनायें और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि बिहार का भाग्य बदलेगा।

इस रैली में केन्द्रीय मंत्रिगण श्री अनंत कुमार, श्री राम विलास पासवान, श्री राधामोहन सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री उपेन्द्र कुशवाहा, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी, पूर्व उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, श्री नंद किशोर यादव, भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडेय सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ■

तापी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण को शुरू करने पर सहमति

पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने तुर्कमेनिस्तान के निर्णय का स्वागत किया, जिसमें दिसम्बर 2015 में पाइपलाइन के तुर्कमेनिस्तान खंड के निर्माण को शुरू करने पर फिर से जोर दिया है। उल्लेखनीय है कि तुर्कमेनिस्तान ने प्रस्ताव किया है कि इसकी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी तुर्कमेनगाज अधिकांश निवेश के साथ तापी परियोजना के लिए समूह का नेतृत्व करेगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 6 अगस्त को अशगाबाट में तापी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की 22वीं संचालन समिति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान इस बात पर सहमति व्यक्त की कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत इस परियोजना में शामिल चार देश हैं और परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठायेंगे। तुर्कमेनिस्तान ने प्रस्ताव किया कि इसकी राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी तुर्कमेनगाज अधिकांश निवेश के साथ तापी परियोजना के लिए समूह का नेतृत्व करेगा।

सभी पक्षों ने तुर्कमेनिस्तान के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता, शेयरधारकों के बीच सहमति और निवेश समझौते की शर्तों पर परियोजना में निवेश करेंगे। श्री प्रधान ने तुर्कमेनिस्तान के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें दिसम्बर, 2015 में पाईपलाईन के तुर्कमेनिस्तान खंड का निर्माण शुरू करने पर फिर से जोर दिया गया है।

श्री प्रधान के साथ भारत के राजदूत, विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, ओवीएल के प्रबंध निदेशक और आईओसी के निदेशक (पाइपलाइन) भी मौजूद थे। ■

केन्द्र की योजनाओं से एक करोड़ युवाओं को जोड़ेगा युवा मोर्चा

भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 अगस्त को दिल्ली में आयोजित पंचक्रांति अभियान की कार्यशाला में घोषणा की कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पांच योजनाओं - स्वच्छता, योग, कन्या-शक्ति, निर्माण

और कौशल जैसे विषयों को लेकर भाजयुमो देश के एक करोड़ युवाओं के बीच ''पंच क्रान्ति अभियान'' चलाएगा। भाजयुमो के इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने किया। कार्यक्रम में श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, केन्द्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री विनय सहस्रबुद्धे जी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा), श्री रामलाल जी (राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, भाजपा), राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा श्री मुरलीधर राव जी, श्री राम माधव जी, श्री अरूण सिंह जी ने पंच क्रांति अभियान के विषय में मार्गदर्शन किया।

श्री एम. वेंकैया नायडू जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण आज पूरा विश्व भारत की ओर बहुत उम्मीदों को साथ देख रहा है। आशा है हम सब मिलकर सुनहरे भारत के निर्माण के लिए इस अभियान में जोर-शोर से काम करेंगे।

श्री रामलाल जी ने युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ से भी अधिक सदस्यों वाला विश्व का सबसे बड़ा राजनैतिक संगठन है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा सही मायने में प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी का सन्देश और उनके सुनहरे भारत की कल्पना को देश के प्रत्येक जन-जन के बीच ले जाने में सफल होगा और 21वीं सदी का विकास आधारित जन-आंदोलन खड़ा करने में अहम भूमिका निभायेगा।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ''पंच क्रांति अभियान'' को देश के प्रत्येक राज्य, जिले और मंडल स्तर तक ले जाया जाएगा जिससे कि देश का हर नागरिक इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के विकास में अपना योगदान दे सके। इस सपने को साकार करने हेतु युवा मोर्चा सभी आधुनिक जन-संचार के माध्यमों विशेष रूप से सोशल मीडिया से देश भर में जागरूकता फैलाना का कार्य करेगा।

श्री ठाकुर ने कहा कि युवा मोर्चा निरंतर देशहित में कार्य करता रहा है। विपक्ष में रहते हुए जहां एक ओर यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाने का विषय हो, देश की अस्मिता और अखंडता को बनाए रखने हेतु कोलकाता से कश्मीर तक की तिरंगा यात्रा कर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का अभूतपूर्व कार्य हो, शहीद सैनिकों के सम्मान में गोहाटी से तवांग तक शहीद श्रद्धांजलि यात्रा का विषय हो, सरहद पर तैनात वीर सैनिकों के सम्मान में देशभक्तिपूर्ण सरहद को प्रणाम का कार्यक्रम हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा हर विषयों पर सक्रिय रहा है। आज जब देश को सुशासन देने वाली भाजपा सरकार जनहित के ऐतिहासिक कार्यक्रम की घोषणा करती है, तो उसको भी जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा तत्पर है। हमारा लक्ष्य देश के एक करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुनहरे भारत की कल्पना के साथ जोड़ने का होगा। ■

'मन की बात'

राजमार्गों पर नकदरहित इलाज की व्यवस्था लागू होगी : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को देश में सड़क दुर्घटना की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना व सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के इलाज के लिए चुनिंदा शहरों व राजमार्गों पर नकदरहित इलाज की व्यवस्था लागू करेगी।

आकाशवाणी पर प्रसारित 'मन की बात' कार्यक्रम में अपने 15 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी दो दिन पहले दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नजर पड़ी। दुर्घटना के बाद वह स्कूटर चालक दस मिनट तक तड़पता रहा। उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात पर लिखते रहते हैं कि मैं सड़क सुरक्षा पर कुछ बोलूं। लोगों को सचेत करूं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई पहल की है। हम सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कार्ययोजना को लागू करने की दिशा में भी हम कई अहम कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और परियोजना हमने ली है, आगे चलकर इसका विस्तार भी होने वाला है, नकदरहित उपचार - गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहां से लेकर मुंबई, रांची, रणगांव, मौंडिया राजमार्गों के लिए, हम एक नकदरहित इलाज व्यवस्था पेश कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने उसका अर्थ भी बताया कि पहले पैसे हैं कि नहीं, पैसे कौन देगा, कौन नहीं देगा, ये सारी चिंता छोड़कर-एक बार सड़क दुर्घटना में जो घायल है, उसे उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, उसे हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में हादसों के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल-फ्री 1033 नंबर, एंबुलेंस की व्यवस्था, ये सारी बातें। लेकिन ये सारी चीजें दुर्घटना के बाद की हैं। दुर्घटना न हो इसके लिए उपाय करना होगा। सचमुच में, एक-एक जान बहुत प्यारी होती है, एक-एक जीवन बहुत प्यारा होता है, उस रूप में उसे देखने की आवश्यकता है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना के कारण, हर चार मिनट में एक मृत्यु होती है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि करीब-करीब एक तिहाई मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देती है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं मां-बाप से गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों को चाहे दो पहिया चलाते हों या चार पहिया चलाते हों, सेफ्टी की जितनी बातें है, उस पर जरूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वे कोई उपदेश नहीं देना चाहते हैं और न ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज की संस्थाओं की इकाइयों की जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता खोज रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने बंगलुरु के अक्षय, पुणे के अमेय जोशी, कर्नाटक के प्रसन्ना काकुंजे के सुझावों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी गांव को 24 घंटे बिजली देना तय करने का वादा किया।

बिजली को प्रगति और हर व्यक्ति के लिए जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि यह कठिन कार्य है लेकिन हमें यह काम शुरू करना है। भारत बड़ा देश है और गांव दूर-दूर हैं लेकिन हम यह करेंगे। इसरो के ब्रिटेन के पांच उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने हालांकि विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विषयों में युवाओं की घटती रुचि पर खेद प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने कानपुर के एक व्यक्ति के सुझाव का जिक्र किया। जिसमें उन्होंने अशक्त लोगों के टिकट बुकिंग के लिए आइआरसीटीसी के पोर्टल पर सुविधा प्रदान किए जाने का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इस सुझाव को गंभीरता से लिया गया और अब इसे लागू कर दिया गया है।■